

प्रेषक,

निदेशक  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार,  
उत्तराखण्ड

देहरादून: दिनांक ०२ फरवरी, २००९

**विषय : जनपद हरिद्वार में पुरानी कबहरी में नवनिर्मित प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या २४०/सू.का/प्रेस क्लब /२००७-०८ दिनांक २२ सितम्बर, २००८ के क्रम में शासनादेश संख्या-१२/XXII /२००७-४(२) २००५ दिनांक १२ जनवरी, २००९ के द्वारा हरिद्वार प्रेस क्लब के भवन निर्माण संबंधी पुनरीक्षित आगणन हेतु टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रुपये ३० लाख (रुपये तीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत करते हुये एवं उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष २००५-०६ में शासनादेश संख्या ३३६/XXII /२००५ दिनांक २० दिसम्बर, २००५ द्वारा अवमुक्त की गयी। रु० १० लाख (रुपये दस लाख मात्र) तथा वर्ष २००७-०८ में शासनादेश संख्या - २५/XXII /२००७-४ (२) २००५ दिनांक ३१ मार्च, २००८ द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रुपये ११.७५ (रुपये ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) कुल धनराशि रुपये २१.७५ लाख (रुपये इक्कीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि घटाते हुये उक्त निर्माण हेतु अवमुक्त की जाने वाली अवशेष रुपये ८.२५ लाख (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिये व्यय हेतु आपके निर्वहन में रखी जाती है।

२ उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता निश्चित आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

३ आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो वरें शिड्यूल आफ रेंट में स्वीकृति नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई है, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करा लें।



4 कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5 एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6 कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0 नि0 पि0 द्वारा प्रचलित दशों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7 निर्माण सामग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्यज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

8 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूमिबेत्ता से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9 निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए। तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/ XIV -219(2006) दिनांक 30.05.2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11 उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2220 रूचना तथा प्रसार-60-अन्य-103-प्रेस सूचना सेवाएँ-03-उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना-00-24-वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

12 उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-123 P /वित्त अनु0-5/2008, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सुबर्द्धन )

निदेशक, सूचना

पत्रांक /सू.एव.लो.सं.वि (प्रेस)/14/2001 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी हरिद्वार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
7. वित्त अनुभाग-5
- ✓ 8. एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

21

( सुबर्द्धन )

निदेशक, सूचना